facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 28 जुलाई 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 01 ● मूल्यः 5 रुपए

अब दिल्ली की रातें भी...

पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि सबसे बड़ी गुरु दुर्गा मां है, यह सत्य है क्योंकि बच्चों की नींव, मां की कोख में बीज मंत्रों से रखी जाती है।

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

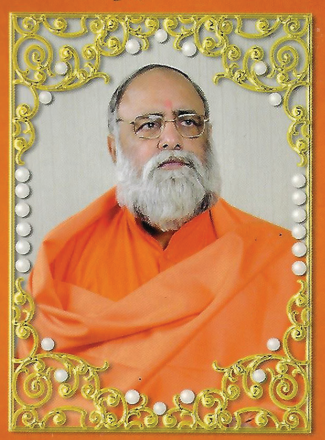

दिव्य पाठ से मस्तिष्क जाग्रत अवस्था में आ जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवाह विद्युत की भांति तरंगित हो उठता है। इसके विवेक को अकल्पनीय ऊर्जा मिलती है।

●

तथाकथित गुरु और संत हमें चिंतन नहीं देते बल्कि भयभीत कर के चिंता दे देते हैं। सच्चा गुरु वही है जो मनुष्य को चिंताओं और भय से मुक्त करे।

●

भौतिक संपन्नता के बावजूद पश्चिम जगत के देश दुखी हैं। केवल अध्यात्म और दिव्या पाठ ही सच्चा सुख प्रदान करने में सक्षम हैं।

ऑपरेशन सिंदूर

से आतंकवाद पर करारा वार

अमित शाह ने लोकसभा में सुनाया 'महादेव' का पूरा लेखा-जोखा

@ भारतश्री ब्यूरो

लोकसभा में मंगलवार को जब गृह मंत्री अमित शाह ने "ऑपरेशन सिंदूर" और "ऑपरेशन महादेव" को लेकर विस्तृत बयान दिया, तो सदन में सन्नाटा था और देशभर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी, शब्दों में तथ्यों की ताकत और उद्देश्य साफ था देश को यह बताना कि अब भारत आतंक पर "डोज़ियर" नहीं, "जवाबी हमला" करता है।

धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या अब नहीं बख्शे जाएंगे

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा कि, "जिस तरह निर्दोष नागरिकों को उनके धर्म पूछकर, परिवार के सामने मारा गया, वह न केवल क्रूरता की चरमसीमा थी, बल्कि मानवता के लिए कलंक भी थी।" उन्होंने कहा, "सरकार और सुरक्षा बलों ने इसका माकूल जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त "ऑपरेशन महादेव" में तीन ए-ग्रेड आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये वही आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में नागरिकों पर हमला किया था।

तीनों आतंकियों की शिनाख्त पूरी तरह पुष्टि के बाद

शाह ने कहा कि मारे गए आतंकियों की पहचान सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिबरान के रूप में हुई है। "इन तीनों के शवों की शिनाख्त उन चार लोगों ने की जिन्हें पहले ही हिरासत में लिया गया था, जो इन्हें रसद पहुंचाते थे। बरामद कारतूसों से भी हमले की पुष्टि हुई।"इन तीनों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। सुलेमान A-श्रेणी का कमांडर था। अफगान और जिबरान भी A-श्रेणी के आतंकवादी थे।

9 आतंकी ठिकानों को किया नेस्तनाबूद

गृह मंत्री ने बताया कि 30 अप्रैल को CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षाबलों को पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी थी। उसके बाद 7 मई को केवल 20 मिनट चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धरती पर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।अमित शाह ने जोर देकर कहा, "इस ऑपरेशन में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मारा गया। केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।" साथ ही बताया गया कि 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया।

"अब डोज़ियर नहीं, सटीक जवाब दिया जाएगा"

शाह ने कहा, "यह मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो सिर्फ फाइलों में डोज़ियर जमा करती रहे। अब भारत हमला करेगा, और जवाब देगा।"उन्होंने बताया कि 9 मई को पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर जवाबी हमला किया गया। इनमें से 8 ठिकानों पर हमले इतने सटीक थे कि पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली तक निष्क्रिय हो गई।

चिदंबरम पर निशाना, विपक्ष की चुप्पी पर तंज

शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "मुझे आशा थी कि पहलगाम हमले के दोषियों के मारे जाने पर पूरा सदन एकजुट होकर सराहना करेगा, लेकिन विपक्ष में चुप्पी छाई रही। क्या आप इस पर खुश नहीं हैं?" उन्होंने पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पूछा था कि "क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे?" अमित शाह ने कहा, "ये सवाल इस देश के पूर्व गृहमंत्री से नहीं, पाकिस्तान के किसी वकील से आने चाहिए थे।"उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, वोटर आईडी नंबर और अन्य दस्तावेज मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे पाकिस्तान से ही आए थे।

"महादेव सिर्फ सैन्य कार्रवाइयां नहीं"

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आतंकियों को उनके अड्डों में घुसकर मारने में संकोच नहीं करता। "हमने न केवल उन आतंकियों को मारा जिन्होंने निर्दोषों को मारा था, बल्कि उनके भेजने वालों को भी बेअसर किया।"उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद वे खुद पीड़ित परिवारों से मिले थे और जो दुख उन्होंने देखा, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता।"ऑपरेशन सिंदूर" और "महादेव" सिर्फ सैन्य कार्रवाइयां नहीं, बल्कि यह संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि कार्रवाई करता है।जहां एक ओर सरकार ने आतंकियों को बारीकी से ट्रैक कर ढेर किया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीक हमले में तबाह कर दिया गया।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

अब दिल्ली की रातें भी महिलाओं की होंगी

नाइट शिफ्ट में काम करने की मिली इजाज़त

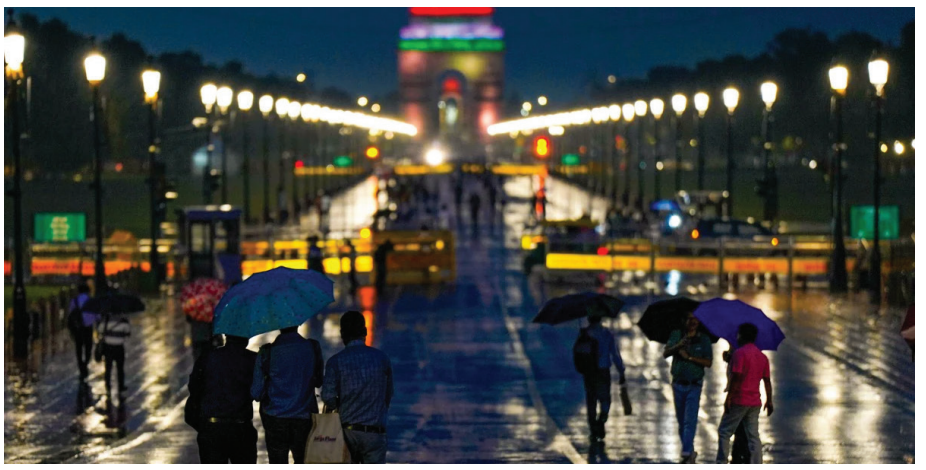

@ मोहित प्रजापति

दिल्ली की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी में अब महिलाएं भी रात्रिकालीन पाली (नाइट शिफ्ट) में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 24x7 यानी चौबीसों घंटे कार्य करने की अनुमति दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस अनुमति के साथ-साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सख्त प्रावधान भी लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि "दिल्ली को 24x7 बिज़नेस हब बनाना है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। हम उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे।"

वेतन और अन्य लाभों के लिए भी स्पष्ट नियम

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन, बोनस, ओवरटाइम भुगतान, और अन्य सभी लाभ पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

वेतन भुगतान केवल बैंक/ईसीएस के माध्यम से।

ईएसआई, पीएफ, बोनस सहित सभी वैधानिक लाभ देना अनिवार्य।

साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम भुगतान और कार्य घंटे की समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

कानून में दी गई छूट

दिल्ली में दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अब तक महिलाओं को गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इस कानून की धारा 14, 15 और 16 में संशोधन कर छूट देने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जा रहा है और इस पर पूर्व चर्चा हो चुकी है। उपराज्यपाल का सहयोग मिलने की पूरी संभावना है।

अन्य राज्यों की तरह दिल्ली भी अब आगे

भारत के कई राज्यों जैसे कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से ही महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य की अनुमति है। अब दिल्ली भी इस पंक्ति में शामिल हो गई है।मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली एक वैश्विक शहर है। यदि हम इसे 24x7 आर्थिक गतिविधियों वाला शहर बनाना चाहते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।" उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी से न केवल आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बल्कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मील का पत्थर होगा।

कड़े सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य किए गए

- महिलाओं को रात में कार्य की अनुमति देने के साथ-साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि काम के स्थान पर महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं:
- रात्रि पाली में कार्य करने से पहले महिलाओं की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
- हर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी।
- परिसर में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे।
- कार्यस्थल पर रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- कार्यस्थल पर POSH कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली में महिलाओं के लिए खुला नया अवसर

दिल्ली की कई पेशेवर महिलाओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। आईटी सेक्टर, हेल्थकेयर, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्री में पहले से ही नाइट शिफ्ट आवश्यक मानी जाती है। ऐसे में महिलाओं को समान अवसर मिलना जरूरी था।साक्षी शर्मा, एक बीपीओ कर्मचारी, कहती हैं, "रात की शिफ्ट में काम करने की इच्छा थी, लेकिन सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहता था। अब सरकार की जिम्मेदारी तय होने से हमें और हमारे परिवार को विश्वास मिलेगा।" सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी इन शर्तों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का श्रम विभाग इस पर नियमित निगरानी करेगा और सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की जाएगी।यह निर्णय न केवल दिल्ली की कार्य संस्कृति को नया आयाम देगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का हिसाब-किताब: खर्च, तुलना और फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर होने वाला खर्च हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। बीते कुछ सालों में उनकी विदेश यात्राओं पर सरकार ने कितना खर्च किया? क्या यह खर्च पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा है या कम? क्या सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी और सार्वजनिक रिपोर्ट्स में कोई अंतर है? और सबसे अहम, क्या इन यात्राओं से भारत को आर्थिक और रणनीतिक फायदा हुआ है? साथ ही, क्या भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के नेता की तुलना में दूसरे देशों के नेताओं के खर्च में कोई समानता या अंतर है? इस लेख में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान और साफ-साफ हिंदी में देंगे।

पांच साल में पीएम मोदी की यात्राओं पर कितना खर्च?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई विदेश यात्राएं की हैं, जो भारत की विदेश नीति को मजबूत करने और ग्लोबल मंच पर देश की साख बढ़ाने के लिए जरूरी मानी जाती हैं। हाल ही में 25 जुलाई 2025 को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि 2021 से 2024 तक पीएम मोदी की 33 विदेश यात्राओं पर कुल 295 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा, 2025 में अब तक पांच देशों (अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, श्रीलंका, और सऊदी अरब) की यात्राओं पर 67 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 2021 से 2025 तक 362 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

कुछ खास यात्राओं का खर्च इस प्रकार है:

2023 में अमेरिका यात्राः 22.89 करोड़ रुपये

2024 में अमेरिका यात्राः 15.33 करोड़ रुपये

2023 में फ्रांस यात्राः 25.59 करोड़ रुपये

2023 में मिस्र यात्रा (विज्ञापन और प्रसारण पर): 11.90 लाख रुपये

2024 में नेपाल यात्रा: 80 लाख रुपये

ये आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ यात्राएं, जैसे अमेरिका और फ्रांस की, काफी महंगी रही हैं, जबकि नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की यात्राएं कम खर्चीली थीं। 2014 से 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार, पीएम मोदी ने 55 महीनों में 92 देशों की यात्रा की, जिन पर कुल 2,021 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें चार्टर्ड फ्लाइट्स, विमानों का रखरखाव, और हॉटलाइन सुविधाएं शामिल थीं।

पहले के पीएम की यात्राओं का खर्च: तुलना कैसी?

पिछले प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं के खर्च की तुलना करें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल (2004-2014) में 93 देशों की यात्राएं कीं, जिन पर कुल 1,350 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, पीएम मोदी ने अपने पहले 55 महीनों में ही 92 देशों की यात्राएं कीं, जिनका खर्च 2,021 करोड़ रुपये रहा।

मनमोहन सिंह (2004-2014): 93 देश, 1,350 करोड़ रुपये

नरेंद्र मोदी (2014-2018): 92 देश, 2,021 करोड़ रुपये

इंदिरा गांधी (15 साल में): 113 देशों की यात्राएं

जवाहरलाल नेहरू (1947-1962): 68 देशों की यात्राएं

हालांकि, पीएम मोदी की चार्टर्ड फ्लाइट्स का खर्च (429.28 करोड़ रुपये) मनमोहन सिंह की तुलना में 64 करोड़ रुपये कम था। लेकिन विमान रखरखाव का खर्च मोदी के कार्यकाल में ज्यादा रहा (1,574.18 करोड़ रुपये बनाम 842 करोड़ रुपये)। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी की यात्राएं बेकार थीं, बल्कि यह दिखाता है कि यात्राओं की संख्या और उनके खर्च में बदलाव आया है। साथ ही, महंगाई और यात्रा से जुड़े दूसरे खर्चों (जैसे सुरक्षा, डेलिगेशन, और प्रचार) में बढ़ोतरी भी इस अंतर का कारण हो सकती है।

RTI और सार्वजनिक रिपोर्ट्स: कितना सच, कितना फर्क?

RTI के जवाब और सार्वजनिक रिपोर्ट्स में कुछ अंतर देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में एक RTI से पता चला कि पीएम मोदी ने 48 महीनों में 41 देशों की 50 से ज्यादा यात्राएं कीं, जिन पर 355 करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन 2018 में ही एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि 55 महीनों में 2,021 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह अंतर क्यों?

डेटा का दायरा: RTI में अक्सर केवल चार्टर्ड फ्लाइट्स, होटल, या सुरक्षा जैसे खास खर्च शामिल होते हैं, जबकि सार्वजनिक रिपोर्ट्स में डेलिगेशन, प्रचार, और उपहार जैसे अतिरिक्त खर्च भी जोड़े जाते हैं।

अपूर्ण जानकारी: कुछ यात्राओं (जैसे 2025 में मॉरीशस, साइप्रस, कनाडा आदि) का खर्च अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है।

पारदर्शिता की कमी: विदेश मंत्रालय ने उपहारों के खर्च को सार्वजनिक करने से मना किया, क्योंकि इससे भारत और दूसरे देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

'द क्विंट' जैसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार प्रेस रिलीज में उपहारों की जानकारी देती है, फिर भी RTI में इसे छिपाने का कोई ठोस कारण नहीं है। इससे जनता में भ्रम पैदा होता है और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

भारत को क्या मिला? आर्थिक और रणनीतिक फायदे

पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनसे भारत को वाकई फायदा हुआ? कई विशेषज्ञों और सरकारी बयानों के अनुसार, इन यात्राओं ने भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूत किया और आर्थिक-रणनीतिक लाभ दिलाए। कुछ प्रमुख फायदे:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने 2018 में बताया कि पीएम मोदी की यात्राओं के बाद 10 देशों से भारत को सबसे ज्यादा FDI मिला। 2014 में FDI 30,930 मिलियन डॉलर था, जो 2017 में बढ़कर 43,478 मिलियन डॉलर हो गया। 2014-2018 के बीच कुल FDI 1,36,077 मिलियन डॉलर रहा, जो मनमोहन सिंह के 2011-2014 के 81,843 मिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है।

मोबिलिटी एग्रीमेंट्स: मोदी की यात्राओं ने इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, और जर्मनी जैसे देशों के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय कुशल श्रमिकों को विदेश में नौकरियां मिलीं।

रणनीतिक साझेदारियां: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे प्रोजेक्ट्स में ग्रीस के पाइरियस बंदरगाह को यूरोप में माल भेजने का केंद्र बनाने की योजना बनी। इसके अलावा, ब्राजील, घाना, और त्रिनिदाद जैसे देशों के साथ व्यापार और रक्षा सौदों ने भारत की ग्लोबल साउथ में पहुंच बढ़ाई।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव: पीएम मोदी ने UN, BRICS, G-20, और SAARC जैसे मंचों पर भारत के विचारों को मजबूती से रखा, जिससे भारत की आवाज वैश्विक मंच पर गूंजी।

हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि इन यात्राओं का खर्च और उनके फायदे का सही हिसाब नहीं दिया गया। विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस, अक्सर सवाल उठाते हैं कि क्या इतना खर्च जायज था। फिर भी, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने 50 करोड़ लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं दीं। यह दिखाता है कि विदेश नीति के साथ-साथ घरेलू विकास पर भी ध्यान दिया गया।

दुनिया के बड़े लोकतंत्रों के नेताओं से तुलना

भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की तुलना में अमेरिका, ब्रिटेन, और जर्मनी जैसे देशों के नेताओं की विदेश यात्राओं का खर्च भी चर्चा में रहता है। हालांकि, सटीक तुलना मुश्किल है, क्योंकि हर देश की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, और यात्रा के उद्देश्य अलग हैं। फिर भी, कुछ उदाहरण:

अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्राएं अक्सर बहुत महंगी होती हैं। उदाहरण के लिए, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब, इजरायल, और यूरोप की यात्रा पर 10 मिलियन डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) खर्च हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा और डेलिगेशन के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां सैन्य और खुफिया संसाधनों का इस्तेमाल होता है।

ब्रिटेन: ब्रिटिश पीएम की यात्राएं अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती हैं। 2019 में बोरिस जॉनसन की G7 समिट यात्रा पर लगभग 2 मिलियन पाउंड (लगभग 20 करोड़ रुपये) खर्च हुए। ब्रिटेन में खर्च की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता ज्यादा है।

जर्मनी: जर्मन चांसलर की यात्राएं भी कम खर्चीली होती हैं। 2022 में ओलाफ शोल्ज की एशिया यात्रा पर लगभग 1.5 मिलियन यूरो (लगभग 13 करोड़ रुपये) खर्च हुए।

भारत की तुलना में अमेरिका और ब्रिटेन में प्रति यात्रा खर्च ज्यादा हो सकता है, लेकिन भारत में यात्राओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही, भारत जैसे विकासशील देश में इतना खर्च विपक्ष के लिए सवाल उठाने का कारण बनता है। फिर भी, भारत की ग्लोबल साउथ में बढ़ती भूमिका और FDI में वृद्धि दिखाती है कि ये यात्राएं बेकार नहीं हैं।

खर्च जायज है या नहीं?

पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च को लेकर बहस हमेशा गर्म रहती है। 2021 से 2025 तक 362 करोड़ रुपये का खर्च निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन पिछले पीएम की तुलना में यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। RTI और सार्वजनिक रिपोर्ट्स में कुछ अंतर दिखता है, जो पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करता है। फिर भी, FDI में बढ़ोतरी, मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, और ग्लोबल मंचों पर भारत की मजबूत मौजूदगी दिखाती है कि इन यात्राओं से देश को फायदा हुआ है।

दूसरे लोकतंत्रों की तुलना में भारत का खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन पारदर्शिता और खर्च के हिसाब में सुधार की जरूरत है। आखिर में, यह सवाल उठता है कि क्या ये खर्च भारत जैसे देश के लिए जायज हैं, जहां अभी भी गरीबी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां हैं? जवाब शायद इस बात में है कि विदेश नीति और घरेलू विकास को एक साथ कैसे बैलेंस किया जाता है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

अब चुप रहो! सरकारी नीतियों पर बोले तो होगी कार्रवाई

सरकारी नीतियों की आलोचना अब वर्जित, सोशल मीडिया पर लगे नए नियम

@ रिंकू विश्वकर्मा

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी राज्य कर्मचारी, अधिकारी या संविदा कर्मचारी न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार की किसी भी मौजूदा या पूर्व नीति की आलोचना सोशल मीडिया पर कर सकेगा। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा जारी नए सरकारी प्रस्ताव (Government Resolution – GR) के तहत लिया गया है, जिसे हाल ही में लागू किया गया है।इन नए नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब व्यक्तिगत और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग रखने होंगे। साथ ही, उन्हें किसी भी प्रतिबंधित मोबाइल एप या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सख्त मनाही होगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की सीमाएं तय

राज्य सरकार ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय कर्मचारियों को बेहद जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा। सरकारी आदेश में बताया गया है कि कर्मचारी अपने अच्छे कामों के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह पोस्ट 'आत्म-प्रशंसा' का रूप नहीं लेनी चाहिए। यानी सरकार अपने कर्मचारियों को आत्म-प्रचार से बचने की सलाह दे रही है।यह नियम केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थानीय निकायों, संविदा कर्मचारियों, और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर भी पूरी तरह लागू होंगे।

सरकारी संपत्तियों की तस्वीरें भी नहीं कर सकेंगे शेयर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी ऐसी पोस्ट साझा नहीं कर सकते, जिसमें सरकारी कार्यालय, सरकारी वाहन, यूनिफॉर्म या सरकारी भवन की तस्वीरें शामिल हों। साथ ही, सरकारी लोगो या पदनाम का भी इस्तेमाल पोस्ट में नहीं किया जा सकता।इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी अपनी वर्दी में, कार्यालय के बाहर या सरकारी गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता। इससे पहले ऐसी तस्वीरें आमतौर पर सोशल मीडिया पर देखी जाती थीं।

आपत्तिजनक और घृणा फैलाने वाली सामग्री पर सख्ती

सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि कोई भी कर्मचारी ऐसी पोस्ट न करे जो आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, मानहानिकारक या नफरत फैलाने वाली हो। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की गतिविधियां सार्वजनिक छवि पर असर डालती हैं, इसलिए संयम और जिम्मेदारी अनिवार्य है।नियमों के उल्लंघन पर महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम, 1979 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

व्यक्तिगत प्रोफाइल में सिर्फ फोटो, बाकी सब पर रोक

सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट में केवल उनकी प्रोफाइल फोटो हो सकती है। अन्य किसी प्रकार की जानकारी, खासकर जो उनके सरकारी काम से जुड़ी हो, उसे साझा करना प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंधित एप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी

नएदिशानिर्देशों में कर्मचारियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी भी मोबाइल एप का उपयोग करने से भी रोका गया है। हालांकि, सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मान्यता प्राप्त मैसेजिंग एप्स के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन केवल ऑफिसियल समन्वय और संवाद के लिए।इसका मकसद यह है कि कर्मचारी सुरक्षित और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें।

सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही चला सकेंगे आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट

अब से किसी भी सरकारी योजना या परियोजना का प्रचार केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें सरकार की ओर से अधिकृत किया गया है। वे भी ऐसा केवल सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही कर पाएंगे। यानी कोई भी सरकारी योजना, अभियान या जनभागीदारी के बारे में पोस्ट तभी की जा सकती है, जब वह एक आधिकारिक माध्यम से हो और इसकी अनुमति हो।

गोपनीय दस्तावेजों को साझा करने पर सख्त रोक

सरकारी आदेश में एक अहम बिंदु यह भी है कि कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के किसी भी गोपनीय दस्तावेज, रिपोर्ट या सरकारी फाइल को सोशल मीडिया या किसी अन्य सार्वजनिक माध्यम पर साझा नहीं कर सकता। न ही आंशिक और न ही पूर्ण रूप से।यह नियम खासकर उन स्थितियों के लिए लागू किया गया है जब किसी विभाग की आंतरिक जानकारी, बजट विवरण या योजनाओं की स्थिति लीक होकर विवाद का विषय बन जाती है।

रिटायरमेंट या ट्रांसफर से पहले अकाउंट सौंपना अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे या स्थानांतरित किए जाएंगे, उन्हें अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी को सौंपना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी अकाउंट का दुरुपयोग न हो और कार्य निरंतरता बनी रहे।

अनुशासन और सरकारी छवि की रक्षा

महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इन नियमों से सरकारी सेवाओं में अनुशासन की भावना मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर अनियंत्रित पोस्ट न केवल व्यक्तिगत छवि को, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी की साख को भी प्रभावित करती हैं।

इन नियमों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल सकारात्मक और उत्पादक कार्यों के लिए करें।महाराष्ट्र सरकार के ये नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल गतिविधियों को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। जहां एक ओर ये नियम सरकारी छवि और गोपनीयता की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल उठता है कि क्या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो रही है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 28 जुलाई 2025, विक्रम संवत 2080

छिपी पहचान और सुरक्षा पर सवाल

यह बात सच है कि भारत में बहुत तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ती रही है, और इस संख्या विस्तार में नेहरू परिवार और कम्युनिस्टों का निरंतर योगदान रहा। अब धीरे-धीरे इन सब लोगों की पोल खुल रही है। अब बांग्लादेशी मुसलमान धीरे-धीरे भाग भी रहे हैं या अनेक मुसलमान ऐसे भी हैं जो भारत में हिंदू नाम से छुपकर रह रहे हैं। अभी-अभी एक आदमी पकड़ा गया है, जिसका नाम 'नेहा किन्नर' है। वह महिला के वस्त्र पहनकर रहता था और अपने को किन्नर बताकर पहचान छुपा रहा था। वास्तव में वह बांग्लादेश का मुसलमान था, जो छिपकर भोपाल में 10 वर्षों से रह रहा था। अब जो खोजबीन हो रही है, उसमें यह मामला पकड़ में आया है। उत्तराखंड में जब खोजबीन शुरू हुई तो सैकड़ों ऐसे मुसलमान मिले जो साधु वेश में थे, जो अपने को हिंदू प्रचारित करते थे लेकिन वास्तव में मुसलमान थे। इस प्रकार के सैकड़ों लोग मिले हैं। 'छांगुर बाबा' का तो सारा भेद खुल ही चुका है। यह भी एक भेद खुला है कि मेरठ के एक मंदिर में कई वर्षों से एक पुजारी था, जो वास्तव में मुसलमान था। उसका पिता कहीं बिहार में मौलवी है और वह व्यक्ति अपना नाम छुपाकर मेरठ में मंदिर में पूजा कराता था। दुर्भाग्य है देश का कि राहुल ब्रिगेड और उनके सहयोगी जैसे अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं कि विदेशी मुसलमानों की जांच न की जाए, उनकी मतदाता सूची न जांची जाए, और सबको भारतीय मान लिया जाए। ऐसे-ऐसे नेता अपने स्वार्थ में इतने बेशर्म हो सकते हैं—यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। जो लोग समाज को धोखा देते हैं, इस तरह के लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और जो लोग किसी स्वार्थवश ऐसे लोगों की वकालत करते हैं, उन राजनीतिक वकीलों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सब लोग ऐसे विदेशी मुसलमानों के समर्थकों का सामाजिक बहिष्कार करें। जरूरत पड़े तो हम ऐसे लोगों का मुंह काला करके भी घुमा सकते हैं, जो इनकी वकालत करते हैं—चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हुए हों। इसलिए मेरा यह मानना है कि सरकार संविधान और कानून के अनुसार कार्य कर रही है और समाज को भी अपने बहिष्कार की ताकत को एक शस्त्र के रूप में उपयोग करना चाहिए।

बजरंग मुनि

भाजपा में संगठनात्मक पुनर्गठन की आहट

@ अनुराग पाठक

भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे रणनीतिक रूप से अहम राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह न सिर्फ आंतरिक लोकतंत्र का संकेत है, बल्कि इससे पार्टी के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की राह भी प्रशस्त होगी।

भाजपा का सांगठनिक ढांचा हमेशा से अनुशासन और कार्यप्रणाली की दृष्टि से अन्य दलों की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित माना जाता रहा है। इसके पीछे एक सशक्त ढांचा और संविधानबद्ध प्रणाली कार्य करती है, जिसमें समय-समय पर संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य रूप से संपन्न कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो, इसके लिए पार्टी हमेशा सजग रहती है।उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर इसका राजनीतिक दबदबा सर्वाधिक है। वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और अब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की संभावना है। सवाल यह है कि क्या पार्टी एक बार फिर सामाजिक समीकरणों के अनुरूप अध्यक्ष चुनने की नीति अपनाएगी, या नए प्रयोग की दिशा में जाएगी ?पूर्व में पार्टी ने पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व देते हुए चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा को देखते हुए, यह चयन अत्यंत रणनीतिक साबित हो सकता है।

गुजरात भाजपा के लिए वैचारिक और राजनीतिक रूप से एक मजबूत आधार रहा है। यहां भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है। सूत्रों के अनुसार, एक-दो दिनों में नाम की घोषणा हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद संगठन के स्तर पर भी नए चेहरों की भूमिका अहम मानी जा रही है।गुजरात की राजनीति में सामाजिक समीकरणों का संतुलन और युवा नेतृत्व का समावेश आगामी नियुक्ति को विशेष महत्व देता है। पार्टी यहां आगामी निकाय चुनाव और फिर 2027 की तैयारी में जुट चुकी है।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति फिलहाल लंबित है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा अब यहां तेजतर्रार और जमीनी पकड़ वाले नेता को कमान सौंप सकती है। साथ ही, लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जिससे नेतृत्व के चयन में सटीकता की अपेक्षा और बढ़ जाती है।

त्रिपुरा में वर्तमान में राजीव भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2022 में माणिक साहा का स्थान लिया था। हालांकि अब पार्टी यहां भी नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी में है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की पकड़ धीरे-धीरे मजबूत हुई है और ऐसे में त्रिपुरा जैसे राज्य में संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। यही कारण है कि पार्टी चरणबद्ध तरीके से पहले प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। यह प्रक्रिया सिर्फ सांकेतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही और सांगठनिक अनुशासन का प्रतीक है।2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027-29 के बीच देश को एक बार फिर संसदीय नेतृत्व चुनना होगा। ऐसे में पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। संगठन को समय रहते सशक्त बनाना, ताकि चुनावी रणनीति की नींव मजबूत रहे।

नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति केवल चेहरों का परिवर्तन नहीं है, यह भाजपा की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा, नई दिशा और नए नेतृत्व का समावेश है। पार्टी एक बार फिर "नए भारत" की राजनीति में संगठित और अनुशासित योगदान देने को तैयार दिख रही है।भाजपा में हो रहा यह सांगठनिक पुनर्गठन आने वाले वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। जहां एक ओर यह बदलाव पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देता है, वहीं दूसरी ओर यह बताता है कि भाजपा चुनावी रणनीति से पहले संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता मानती है। और शायद यही उसकी लगातार सफलता का एक बड़ा कारण भी है।

जुबानी तीर

"यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए किया गया था। पायलटों के हाथ बांध दिए गए थे, उन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई।

राहुल गांधी (कांग्रेस सांसद, नेता विपक्ष – लोकसभा)

"हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और रणनीति का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान खुद ceasefire की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। यह भारत की कूटनीतिक और सामरिक विजय है।

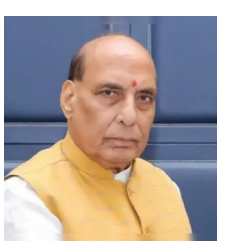

राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री)

"कांग्रेस को सेना का अपमान करने की आदत हो गई है। राहुल गांधी बार-बार देश के हीरो को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये वही मानसिकता है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती थी।

अमित शाह (गृह मंत्री)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

दांतों के दर्द का आयुर्वेदिक इलाज

जड़ से समाधान, बिना साइड इफेक्ट के

आधुनिक चिकित्सा में दर्दनिवारक दवाएं या रूट कनाल जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं, लेकिन यदि आप एक प्राकृतिक, सुरक्षित और स्थायी समाधान की तलाश में हैं, तो आयुर्वेदिक इलाज एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

@ डॉ महिमा मक्कर

दांतों का दर्द एक सामान्य लेकिन बेहद कष्टदायक समस्या है, जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यह दर्द अचानक आ सकता है और खाना, पीना, बोलना तक मुश्किल कर देता है। आधुनिक चिकित्सा में दर्दनिवारक दवाएं या रूट कनाल जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं, लेकिन यदि आप एक प्राकृतिक, सुरक्षित और स्थायी समाधान की तलाश में हैं, तो आयुर्वेदिक इलाज एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

आयुर्वेद — भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति , शरीर को संतुलन में रखकर रोगों का उपचार करती है। इसमें दांतों के दर्द (दन्तशूल) का इलाज जड़ी-बूटियों, तेलों, दिनचर्या और खान-पान के माध्यम से किया जाता है, जिससे समस्या की जड़ तक पहुँचा जा सकता है।

दांतों के दर्द के संभावित कारण

आयुर्वेद के अनुसार, दांतों का स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ – इन तीन दोषों के संतुलन पर निर्भर करता है। जब इनमें से कोई भी दोष असंतुलित होता है, तो यह दांतों व मसूड़ों में दर्द या संक्रमण का कारण बन सकता है।

मुख्य कारण:

वात दोष का बढ़ना – ठंडा खाना, अधिक उपवास या कमजोर पाचन से वात बढ़ता है जिससे दर्द तीव्र होता है।

पित्त दोष का असंतुलन – तीखा, खट्टा या गरम भोजन पित्त को बढ़ाता है, जिससे सूजन और जलन होती है।

कफ दोष का बढ़ना – तैलीय, भारी और ठंडे भोजन से कफ बढ़ता है, जिससे पस या संक्रमण हो सकता है।

आयुर्वेदिक घरेलू उपचार

1. लौंग का तेल (Clove Oil)

लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक है।

उपयोग:

- रुई में लौंग का तेल लगाकर दर्द वाले दांत पर रखें।
- दिन में 2-3 बार दोहराएं।

2. त्रिफला माउथवॉश

त्रिफला एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक मिश्रण है जो संक्रमण को रोकने और मसूड़ों को मजबूत करने में मदद करता है।

उपयोग:

- 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करें।

3. हल्दी और नमक का पेस्ट

हल्दी एंटीबैक्टीरियल और सूजनरोधी है, जबकि सेंधा नमक दर्द और सूजन को कम करता है।

उपयोग:

- हल्दी पाउडर और सेंधा नमक में सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और दांतों पर लगाएं।

4. गुणकारी जड़ी-बूटियां

बबूल की छाल – इससे ब्रश करने से मसूड़े मजबूत होते हैं।

नीम की दातुन – नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं।

अर्जुन की छाल – हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है।

दिनचर्या और जीवनशैली में बदलाव

आयुर्वेद में उपचार केवल जड़ी-बूटियों से नहीं होता, बल्कि जीवनशैली को संतुलित कर के भी किया जाता है। यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन करें, तो दांतों की समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।

दिनचर्या में अपनाएं:

रोज़ सुबह और रात नीम, बबूल या त्रिफला पाउडर से ब्रश करें।

हर भोजन के बाद कुल्ला करें।

अत्यधिक मीठा, चिपचिपा व ठंडा भोजन टालें।

धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करें।

सुबह उठकर तिल तेल से "तेल कुला" करें – यह मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है।

आहार में सुधार

आप जो खाते हैं, वह आपके दांतों की सेहत को सीधा प्रभावित करता है। इसलिए दांतों की रक्षा के लिए संतुलित और दोषानुसार आहार जरूरी है।

अनुशंसित आहार:

गुनगुना पानी पीना

हरी पत्तेदार सब्जियां

फाइबर युक्त फल जैसे सेब, अमरूद

ताजे मसाले – हल्दी, जीरा, अदरक

बचाव हेतु टालें:

बहुत अधिक मिठाई और ठंडा पेय

बासी या प्रसंस्कृत (processed) खाद्य पदार्थ

अत्यधिक तैलीय या मसालेदार खाना

कब डॉक्टर के पास जाएं?

अगर घरेलू उपायों से 2–3 दिन में आराम न मिले, या निम्न में से कोई लक्षण हो, तो तुरंत आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें:

तेज़ बुखार के साथ दर्द

सूजन, मवाद या पस निकलना

लगातार खून आना

जबड़ा खोलने में कठिनाई

दांतों का दर्द केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक तनाव और दैनिक जीवन की कठिनाइयों को भी बढ़ा सकता है। आयुर्वेद न केवल इस दर्द का इलाज करता है, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलन में लाकर दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है।यदि आप रासायनिक दवाओं और उनके दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक उपचार जड़ी-बूटियों, दिनचर्या और खानपान के संतुलन के माध्यम से एक प्रभावशाली और सुरक्षित विकल्प है।

संत गुलाल साहब: प्रेम और भक्ति का आलोक

संत गुलाल साहब सत्तनामी संतों की पवित्र परंपरा में एक चमकता सितारा हैं। उनकी वाणी में भक्ति की मधुरता, प्रेम की गहराई और आत्मज्ञान का प्रकाश झलकता है। उन्होंने अपनी साधना और अनुभवों को सरल, सहज और हृदय को छूने वाली भाषा में व्यक्त किया। उनके जीवन का हर क्षण भगवद्भक्ति और सत्संग में डूबा हुआ था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब देश में राजनैतिक अशांति और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था, संत गुलाल साहब ने अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से जनमानस को शांति, प्रेम और अध्यात्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

प्रारंभिक जीवन: भुरकुड़ा में जन्मा एक साधारण गृहस्थ

संत गुलाल साहब का जन्म संवत् 1750 में उत्तर भारत के गाजीपुर जनपद के वैसहरि मंडल के भुरकुड़ा गांव में हुआ। वे एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और एक साधारण जमींदार के रूप में जीवन यापन करते थे। खेती-बाड़ी उनकी आजीविका का साधन थी, लेकिन उनका हृदय सदा साधु-संतों की सेवा और भक्ति में रमा रहता था। उनकी सहजता और साधुओं के प्रति श्रद्धा ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी।

उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी। यह घटना उनके हलवाहे बुलाकी राम के साथ जुड़ी है, जो बाद में उनके गुरु बने। एक दिन गुलाल साहब खेतों में बुलाकी राम का काम देखने गए। उन्होंने देखा कि बुलाकी राम हल छोड़कर ध्यानमग्न बैठे हैं और बैल खेत में खड़े हैं। गुलाल साहब को गुस्सा आया और उन्होंने बुलाकी राम की पीठ पर लात मार दी, यह सोचकर कि वह कामचोरी कर रहा है। लेकिन जब बुलाकी राम का ध्यान टूटा, तो गुलाल साहब ने देखा कि उनके हाथ से दही छलक रहा था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने इसका कारण पूछा। बुलाकी राम ने डरते हुए कहा कि वह संतों की सेवा में व्यस्त थे और दही परोस रहे थे। यह सुनकर गुलाल साहब का हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत बुलाकी राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा मांगी। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया।

गुरु की कृपा: बुलाकी राम से दीक्षा

बुलाकी राम, जो प्रसिद्ध संत बुल्ला साहब के नाम से जाने जाते थे, ने गुलाल साहब को दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बनाया। बुल्ला साहब ने गुलाल साहब को गुरुतत्व का बोध कराया और भगवन्नाम की महिमा समझाई। इस दीक्षा ने गुलाल साहब के जीवन में एक नया प्रकाश जला दिया। उनकी एक उक्ति इस अनुभव को खूबसूरती से व्यक्त करती है:

खोजत-खोजत सतगुरु पावल, ताहि चरनवाँ चितवा लागल हो सजनी।

साँझि समय उठि दीपक वारल, कटल करमवाँ मनुवाँ पागल हो सजनी।

इस दोहे में गुलाल साहब ने सतगुरु की खोज और उनके चरणों में समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। बुल्ला साहब ने भुरकुड़ा में रहकर अपने शिष्यों को भगवन्नाम की साधना और सत्संग का महत्व समझाया। गुलाल साहब ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधना को अपनाया और सतगुरु की कृपा से संसार की आसक्ति से मुक्त हो गए। उनकी एक और उक्ति इस भाव को दर्शाती है:

सतगुरु किरपा अगम भयो हो, हिरदय बिसराम।
अब हम सब बिसरावल हो, निस्चय मन राम।

भक्ति और साधना: राम-नाम की महिमा

संत गुलाल साहब का जीवन भगवन्नाम की साधना के इर्द-गिर्द घूमता था। उन्होंने बार-बार अपने उपदेशों में कहा कि भगवन्नाम का जप ही भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है:

सुर नर नाग मनुप औतार, विनु हरि भजन न पावहिं पार।

उनका मानना था कि राम का दर्शन बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर ही करना है। राम ही परमानंद का सागर और कल्याण का कल्पवृक्ष हैं। गुलाल साहब ने भगवत्-तत्व की गहरी समझ विकसित की और सच्चिदानंद ब्रह्म की साधना में निरंतर लीन रहे। उनकी एक मार्मिक रचना इस भाव को व्यक्त करती है:

लागलि नेह हमारी, पिया मोर।
चुनि-चुनि कलियाँ सेज विछावो, करो मै मगलाचार।
एकौ घरी पिया नहि अइलें, होइला मोहिं धिरकार।

इस रचना में गुलाल साहब ने भगवान के प्रति अपनी प्रेममयी भक्ति और उनके दर्शन की तड़प को व्यक्त किया है। उनकी साधना का आधार निर्मल ज्ञान और अखंड ब्रह्म की अनुभूति थी। उन्होंने भगवान को अजर, अमर और अविनाशी बताया, जो न तो जन्म लेते हैं, न नष्ट होते हैं, और न ही उन्हें चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है।

रचनाएँ: भक्ति की मधुर वाणी

संत गुलाल साहब की रचनाएँ भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनकी वाणी में सत्संग की महिमा, भगवन्नाम की शक्ति और सतगुरु के प्रति समर्पण का भाव गहराई से झलकता है। उनकी रचनाओं का एक संग्रह उपलब्ध है, जिसमें उनके दोहे, पद और भक्ति भरे भजन शामिल हैं। उनकी रचनाएँ सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं, जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श करती हैं। उनकी एक रचना में वे कहते हैं:

गगन, मगन धुनि गाजे हो, देखि अघर अकास।
जन 'गुलाल' बँसहरिया हो, तह करहि निवास।

इस दोहे में गुलाल साहब ने भगवन्नाम की साधना को आकाश की तरह विशाल और मन को मगन करने वाला बताया है। उनकी रचनाएँ संत-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनकी वाणी में प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का ऐसा संगम है, जो सुनने वाले को तुरंत ईश्वर की ओर ले जाता है। उनकी रचनाएँ न केवल भक्ति की प्रेरणा देती हैं, बल्कि सतगुरु और संतों के प्रति श्रद्धा को भी बढ़ाती हैं।

संतों के प्रति श्रद्धा: सत-चरण की महिमा

गुलाल साहब का संतों और सतगुरु के प्रति अटूट विश्वास था। उनका कहना था कि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। संतों की संगति से नीच से नीच व्यक्ति भी परमपद को प्राप्त कर सकता है। उनकी एक उक्ति इस भाव को व्यक्त करती है:

सत-चरण-कमल की महिमा का बखान करना मेरे वश की बात नही है।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्त के पीछे-पीछे चलते रहते हैं।

उनका मानना था कि सतगुरु की कृपा से ही भक्त भगवान के चरणों तक पहुँच सकता है। उनकी साधना और उपदेशों का मूल आधार यही था कि सत्संग और भगवन्नाम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।

अंतिम समय और विरासत

संत गुलाल साहब ने संवत् 1816 में देह त्याग किया। अपने अंतिम समय तक वे लोगों को संसार के नश्वर स्वरूप को समझाते रहे। वे परम गुरुभक्त, भगवन्निष्ठ और असाधारण तत्वज्ञानी थे। उनकी शिक्षाएं और रचनाएँ आज भी भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके शिष्य और अनुयायी, जैसे जगजीवन साहब, ने उनके सत्तनाम के संदेश को और आगे बढ़ाया। गुलाल साहब ने भुरकुड़ा में शांति और सत्य की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की, जो आज भी भक्तों के हृदय को रोशन करती है।

भक्ति का अमर प्रकाश

संत गुलाल साहब का जीवन एक तपस्वी, भक्त और तत्वज्ञानी का जीवन था। उन्होंने अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से यह सिखाया कि भगवन्नाम की साधना ही जीवन का सच्चा सुख है। उनकी वाणी में प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का ऐसा समन्वय है, जो हर भक्त को ईश्वर के करीब ले जाता है। उनकी रचनाएँ संत-साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो भक्ति की मधुर धारा को प्रवाहित करती हैं। गुलाल साहब का जीवन हमें सिखाता है कि सतगुरु की कृपा और भगवन्नाम की शक्ति से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। उनका जीवन और उनकी रचनाएँ हमें सदा भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर लोकसभा में गरमागरम बहस

संसद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन

@ मनीष पांडेय

लोकसभा में सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर सेना के मनोबल को तोड़ने और आतंकवाद पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया।

विपक्ष के किसी सांसद ने हमले की असलियत नहीं बताई

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने आतंकी हमले पर चर्चा तो की, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आतंकियों ने हमला करते समय पीड़ितों से धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को मजबूर किया और उनकी पहचान जानकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने सवाल किया, "क्या विपक्ष के लिए यह बताना कठिन था? जब रक्षामंत्री हमारी सेना की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, तब विपक्ष की बेंचों पर कोई तालियां नहीं बजीं, न ही मेजें थपथपाई गईं।"

मोदी सरकार ने दिया आतंकियों को करारा जवाब

अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि 7 मई को भारतीय सेना ने केवल 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ठाकुर ने कहा, "हमने यह संदेश दिया कि भारत पर आतंकी हमला, भारत पर सीधा हमला माना जाएगा। अब भारत डोज़ियर नहीं, सीधे डोज़ देगा। यह नया भारत है, और आतंकवाद पर यह नया सामान्य है।"

रहीम खान एयरबेस अब बैलगाड़ी लायक भी नहीं

ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित रहीम खान एयरबेस पर ऐसा हमला किया कि अब वह बैलगाड़ी लायक भी नहीं बचा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "हमारी सेना वहां वार करती है, जहां दुश्मन को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। यह बात राहुल गांधी तक जरूर पहुंचा दीजिए।"

पाकिस्तान की तारीफ, सेना की निंदा... कांग्रेस का असली चेहरा उजागर

भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अगर आपको हमारी सेना पर भरोसा नहीं है, तो पाकिस्तान जाकर पूछ लो, जिसकी शान में आप (कांग्रेस) दिन-रात कसीदे पढ़ते हैं।" ठाकुर ने 26/11 हमले का हवाला देते हुए कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार अंतरराष्ट्रीय अनुमति का इंतजार करती रही, जबकि आज की सरकार बिना किसी देरी के जवाब देती है।

सेना का बजट तीन गुना हुआ, मेड इन इंडिया बुलेटप्रूफ जैकेट बनीं

उन्होंने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा द्वारा उठाए गए रक्षा बजट के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय रक्षा बजट करीब 2.5 लाख करोड़ था, जबकि अब यह 6.81 लाख करोड़ हो गया है। ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार बुलेटप्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाई थी, जबकि मोदी सरकार ने तीन साल में मेड इन इंडिया जैकेट सेना को उपलब्ध करवाई।

कांग्रेस ने सेना का मनोबल गिराया, पाकिस्तान को मजबूती दी

ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ सेना का अपमान किया, बल्कि पाकिस्तान के हौसले भी बढ़ाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आर्मी चीफ को 'सड़क का गुंडा' कहा था। राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए ठाकुर बोले, "कांग्रेस ने बाटला हाउस मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। कांग्रेस सेना के साथ नहीं, आतंकियों के लिए आंसू बहाती है।"

"राहुल गांधी एलओपी नहीं, एलओबी हैं"

राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें जनता ने कभी इतना समर्थन नहीं दिया कि वे विपक्ष के नेता बन सकें। उन्होंने तंज कसा, "राहुल गांधी एलओपी नहीं, एलओबी हैं – यानी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सबूत मांग रहे थे। "ऐसे लोगों से देश को क्या उम्मीद हो सकती है?" ठाकुर ने कहा।

आईएनसी अब बन गई है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस की कूटनीति सिर्फ डोज़ियर तक सीमित थी, कार्रवाई तक नहीं पहुंची। जबकि हमने सेना के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया जिसे दुनिया ने देखा।"

"कांग्रेस का इतिहास है सरेंडर और ब्लंडर का"

कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसलों पर सवाल उठाते हुए ठाकुर ने कहा कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, अक्साई चिन को चीन को सौंपना और कच्चा तिब्बू द्वीप श्रीलंका को देना कांग्रेस के ऐसे सरेंडर हैं जो देश को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की विदेश नीति में आत्मविश्वास की कमी थी, जबकि मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाया।"

अनुराग ठाकुर का लोकसभा में दिया गया भाषण न केवल सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों का समर्थन करता दिखा, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ न केवल आक्रामक रुख अपना रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी ताकत का अहसास करा रहा है। लोकसभा की यह बहस एक बार फिर दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे देश की राजनीति में कितने केंद्रीय विषय बन चुके हैं और इन पर सियासत भी उतनी ही तीखी होती जा रही है।

परमात्मा से मिलाते हैं गुरुदेव जी

पू. सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बन्तो कटारिया जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि सबसे बड़ी गुरु दुर्गा मां है, यह सत्य है क्योंकि बच्चों की नींव, मां की कोख में बीज मंत्रों से रखी जाती है। मां ही सृष्टि का निर्माण करने वाली है अत: सबसे पहले वही हमारी गुरु है। उसके बाद स्कूल में अध्यापक गुरु है और शादी हो जाने के बाद गुरु चुनने का अधिकार बच्चे को हो जाता है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को परमात्मा से मिला दे। आज के कलयुग में आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। मैं यहां पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या को देखकर कह सकती हूं कि भक्त नहीं होते तो भगवान भी नहीं होता और संत और गुरुदेव भी नहीं होते। जैसे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था वैसे ही आप भी हमें दिखा रहे हैं आपको कोटि-कोटि नमन।

कलिन को जानकर परिहार करके पाठ करें

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिवस माता की विशेष कृपा प्रदान करने वाला है। दुर्गासप्तशती में वर्णन है कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने यह पाठ कीलित कर रखा है। जो मनुष्य कीलन को जानकर, उसका परिहार करके ही पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर, उसका परिहार करके ही पाठ करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मां भगवती की सेवा में होकर न्यायपूर्वक कमाया हुआ अपना धन उनके चरणों में समर्पित करना और फिर उसे प्रसादरूप से ग्रहण करना भी निष्कीलन अथवा शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है।इसका अर्थ यह है कि भक्त हमेशा देवी मां भगवती की आधीनता में रहे और जो भी वह अर्जित करे उसे प्रसादरूप में ग्रहण करे। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी मां के प्रसाद का ही फल हैं इस कल्याणमय का पाठ साथ ही करते रहना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी मां के पाठ को और स्तुति को मनुष्य क्यों नहीं करते?

सबका आत्मा एक है

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि सबका आत्मा एक है। यह स्थिर है तथा कहीं आता-जाता नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां है, वहां है, भटक रही है, यह गलत है। आत्मा शाश्वत और सदा रहने वाली है। गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा न शस्त्र से कटती हे, न आग में जलती है, न हवा इसे सुखा सकती है, न पानी इसे गला सकता है। जो लोग भूत-प्रेत की बात करते हैं वह सब निराधार है जबकि किसी को अपनी आत्मा का भी नहीं पता।

भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महामंत्री व मंच संचालक श्री सुशील वर्मा 'गुरुदास' जी ने कहा कि आज कब से प्यासे भाई-बहनों की आस पूरी हुई है। जैसे अमृतसर में अमृत का सरोवर है वैसे ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी व गुरु मां जी के दर्शनों का महाअमृत यहां प्रकट हुआ है और अनायास दुर्लभ कृपा हुई है। पंजाब सत्गुरुओं की पावन धरती है। जालंधर भी शौर्य, भक्ति और सेवा की अद्भुत धरती है। जालंधर का अद्भुत इतिहास है और आपका प्रेम तो शब्दातीत है। आपका अनन्य निर्मल प्रेम है। आप कब प्यास हैं सद्गुरु के दर्शन के।

अनेक रोगों का निवारण होता है मिरेकल वंडर वाश से

ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस डा. सुमिता सिंह ने बताया कि हमने देखा है कि ज्यादातर महिलाएं जो यूटीआई से ग्रस्त हैं, उन्हें व्हाइट डिचार्ज होता है और पानी गिरता है। वे कहती हैं कि हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और इंफेक्शन की प्राब्लम होती है। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। डाक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। सारे शरीर में दर्द होता है। हमने आज 500 मरीजों को देखा जिन्हें पानी गिरने की प्राब्लम थी और वे लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस बताती थीं। लोअर बैक में पैन भी बताती थी। पिछले सत्संग में हमने एक ग्रोथ देखी थी कि एक्ट्रा मांस बढ़ा हुआ था लेकिन जैसे ही मिरेकल वंडर वाश लगाया वह सिकुड़ गया। वहां जो लाली थी वह भी एक मिनट बाद कम हो गई। आज मैक्सिमम बहनों का एक्सपीरियंस यह था कि हमको बहुत लाईट और अच्छा फील हो रहा है।

25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में भारत सरकार ने 25 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है, जिन पर अश्लील, आपत्तिजनक और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने का आरोप है। यह फैसला 23 जुलाई 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा लिया गया, जिसमें कई सरकारी विभागों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। इस कदम ने न केवल डिजिटल कंटेंट की दुनिया में हलचल मचाई है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। इस लेख में हम इस बैन के पीछे के कारण, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की चिंताओं, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाओं, और इसके व्यापक प्रभावों को आसान और रोज़मर्रा की हिंदी में समझेंगे।

बैन का कारण: अश्लील कंटेंट की बाढ़

सरकार ने जिन 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, उनमें ULLU, ALTT, Desiflix, Big Shots App, Boomex, MoodX, NeonX VIP, Mojflix, Triflicks, Gulab App, Hulchul, और HotX VIP जैसे नाम शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर 'सॉफ्ट पोर्न' कंटेंट दिखाने का आरोप है, जो वेब सीरीज़ के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। सरकार के मुताबिक, इनका कंटेंट न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचा रहा था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट में ज्यादातर ग्राफिक सेक्शुअल सीन, न्यूडिटी, और बिना किसी कहानी या सामाजिक संदेश के पोर्नोग्राफिक दृश्य थे। कुछ मामलों में, इनमें पारिवारिक रिश्तों को गलत तरीके से दिखाया गया, जो नैतिकता और कानूनी सीमाओं को पार करता था। मंत्रालय ने कहा, "इन शोज़ में न तो कोई कहानी थी, न थीम, और न ही कोई सामाजिक संदेश। यह सिर्फ बोल्ड और अनुचित विज़ुअल्स पर फोकस था।"

यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के आधार पर की गई। इन प्लेटफॉर्म्स की 26 वेबसाइट्स और 14 मोबाइल ऐप्स (9 गूगल प्ले स्टोर और 5 ऐप्पल ऐप स्टोर पर) को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया।

पिछले कुछ समय से सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को कई बार चेतावनी दी थी। सितंबर 2024 में सभी 25 प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा गया, और फरवरी 2025 में IT नियम 2021 के तहत कोड ऑफ एथिक्स का पालन करने की सलाह दी गई। फिर भी, इन प्लेटफॉर्म्स ने आपत्तिजनक कंटेंट दिखाना जारी रखा। कुछ ने तो मार्च 2024 में बैन होने के बाद नए डोमेन बनाकर फिर से वही कंटेंट अपलोड किया।

NCW और NCPCR की चिंताएं: बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इन OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर गहरी चिंता जताई थी। ये दोनों संस्थाएं इस मामले में पहले से ही सक्रिय थीं और इन्होंने सरकार को कई बार चेतावनी दी थी।

NCW की चिंताएं

NCW ने खास तौर पर ULLU के वेब सीरीज़ "House Arrest" पर सवाल उठाए, जिसमें पारिवारिक रिश्तों को गलत तरीके से दिखाया गया और महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन (वस्तुकरण) किया गया। NCW ने ULLU डिजिटल के प्रतिनिधियों को समन भेजकर पूछा, "अगर आपका बच्चा ऐसा कंटेंट देखे तो क्या होगा?" आयोग ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे कंटेंट को नहीं रोका गया तो गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी।

NCW का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट में महिलाओं को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जो समाज में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आयोग ने इसे "महिलाओं के अश्लील चित्रण" के खिलाफ कानून का उल्लंघन माना।

NCPCR का रुख

NCPCR ने बच्चों के लिए खतरे पर जोर दिया। आयोग ने जुलाई और अगस्त 2024 में ULLU और ALTT के कंटेंट को बच्चों के लिए हानिकारक बताया। NCPCR ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन या प्रोफाइल लॉक नहीं है, जिससे बच्चे आसानी से अश्लील कंटेंट तक पहुंच सकते हैं।

NCPCR ने सितंबर 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर OTT प्लेटफॉर्म्स पर डिस्क्लेमर लगाने की मांग की थी। इसमें POCSO एक्ट की धारा 11 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर बच्चे अडल्ट कंटेंट देखते हैं तो सब्सक्राइबर्स को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

NCPCR ने यह भी बताया कि बच्चों द्वारा अश्लील कंटेंट देखने के बाद अपराध करने के मामले बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 में भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) के साथ बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाः समर्थन से लेकर विरोध तक

इस बैन पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कुछ ने इसे जरूरी कदम बताया, तो कुछ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।

समर्थन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) और इसके सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने इस बैन का स्वागत किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल अक्टूबर में ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन की मांग की थी। उनका कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स अश्लीलता और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ कंटेंट फैला रहे हैं।

कई बीजेपी नेताओं ने इसे बच्चों और समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर अश्लीलता और गलत कंटेंट न फैलाएं।"

विरोध

कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला ने इस बैन की आलोचना की और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने दावा किया कि सरकार चुनिंदा तरीके से उन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रही है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। शुक्ला ने कहा, "अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई गलत है।"

कुछ अन्य विपक्षी नेताओं, जैसे शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, ने भी इस मुद्दे को संसद की स्टैंडिंग कमेटी में उठाया था। उन्होंने ULLU की वेब सीरीज़ "House Arrest" में अजाज़ खान के विवादास्पद क्लिप पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बैन को पूरी तरह सही नहीं माना।

सामाजिक संगठनों और जनता की प्रतिक्रिया: हलचल और मीम्स

सामाजिक संगठनों और जनता ने भी इस बैन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी बताया, तो कुछ ने इसे सेंसरशिप का हथियार माना।

सामाजिक संगठनों का रुख

सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने इस बैन का समर्थन किया। फाउंडेशन के प्रमुख उदय महुरकर ने कहा कि ऐसे कंटेंट "भारत के सांस्कृतिक ढांचे को नष्ट करने वाले गैरकानूनी कृत्य" हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसे मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की मांग की।

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने ULLU और "House Arrest" की कड़ी निंदा की। उनके अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने इसे "सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक" बताया और बैन की मांग की थी।

जनता की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया, खासकर X पर, इस बैन को लेकर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। कई यूज़र्स ने इसे "बेस्ट डिसीजन" करार दिया और सरकार की तारीफ की। एक यूज़र ने लिखा, "वेल डन, गवर्नमेंट! ULLU, ALTT जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन करना जरूरी था।"

वहीं, कुछ यूज़र्स ने इसे सेंसरशिप का मुद्दा बनाया। एक X यूज़र ने लिखा, "बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। X, Reddit, और Telegram पर भी तो ऐसा कंटेंट उपलब्ध है। बेहतर रेगुलेशन की जरूरत है।" दूसरों ने मीम्स और जोक्स बनाकर इस बैन का मज़ाक उड़ाया, जैसे "हम करते हैं प्रबंध" जैसे कमेंट्स।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

प्राचीन हिंदू मंदिर बना जंग का मैदान

थाईलैंड–कंबोडिया सीमा पर हिंसा, एयरस्ट्राइक और मौत का तांडव

@ सुमित शुक्ल

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच वर्षों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर उग्र हो उठा है — और इस बार केंद्र में है एक प्राचीन हिंदू मंदिर, जिसे लेकर दोनों देशों में खूनी संघर्ष छिड़ गया है। गुरुवार से जारी हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और नागरिक भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों घायल हैं। मंदिर के आसपास के गांव खाली कराए जा रहे हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयरस्ट्राइक तक कर दी है।इस संघर्ष ने न सिर्फ दो देशों के राजनयिक संबंधों को झकझोर दिया है, बल्कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए मंदिर क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुँची है। इसके मद्देनज़र कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है।

झड़प की शुरुआत और हिंसा की चिंगारी

थाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुरासंत कोंगसीरी के अनुसार, यह संघर्ष गुरुवार को सीमा के कम से कम छह अलग-अलग इलाकों में शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले थाईलैंड के पांच सैनिक एक लैंडमाइन विस्फोट में घायल हो गए थे। थाई सेना का दावा है कि यह लैंडमाइन "नया और रूसी तकनीक" का था, जिसे उन्होंने कंबोडिया द्वारा लगाया गया बताया।

इस घटना के बाद थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया और अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। वहीं, कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए थाईलैंड पर 'आक्रामक रुख' अपनाने का आरोप लगाया और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा।

ता मुएन थोम मंदिर के पास जबरदस्त लड़ाई

संघर्ष का मुख्य केंद्र बना है ता मुएन थोम मंदिर और प्रीह विहेयर मंदिर क्षेत्र, जहां दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ गए। कंबोडिया के ओडर मींचे प्रांत के प्रमुख जनरल खोव ली के अनुसार, शुक्रवार सुबह संघर्ष फिर से शुरू हुआ। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि सीमा के पास तोपों की आवाज और रॉकेटों की गूंज सुनाई दी।

कंबोडिया ने दावा किया कि थाईलैंड के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने दो बार बमबारी की, जिसमें प्राचीन मंदिर के पास की सड़कें और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं।

नागरिकों का पलायन और मौतें

थाई सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1 सैनिक और 13 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 सैनिक और 32 अन्य नागरिक घायल हैं। हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचायाचाई ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि सीमा से कम से कम 50 किमी तक का क्षेत्र खाली कराया जाए।

कंबोडिया की अपील और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ले. जनरल माली सोचेता ने थाई कार्रवाई को "सीमा उल्लंघन" बताया और कहा कि कंबोडियाई सेना ने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र भेजकर "थाई आक्रमण" पर आपात बैठक बुलाने की मांग की।यूएन सुरक्षा परिषद ने भी शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक बंद बैठक निर्धारित की, जिससे यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष वैश्विक चिंता का विषय बन गया है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद की जड़ें

इस संघर्ष की जड़ें प्राचीन हिंदू मंदिर 'प्रीह विहेयर' (Preah Vihear Temple) से जुड़ी हैं। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का है और शिवजी को समर्पित खमेर वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। यह मंदिर डांगरेक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और भौगोलिक रूप से सीमा पर आता है।कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उसकी सीमा में है, जबकि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार थाईलैंड की ओर है। यही विवाद की मुख्य वजह है।

अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला और फिर भी विवाद

1962 में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था। हालांकि, मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किमी भूमि पर थाईलैंड का दावा आज भी बना हुआ है।2008 में जब यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया, तो थाईलैंड ने इसका विरोध किया। उसे आशंका थी कि यह कंबोडिया के दावे को वैधता प्रदान करेगा।

2008–2011 के बीच झड़पें और वर्तमान की पुनरावृत्ति

विवाद तब और भड़क गया जब 2008 से 2011 के बीच मंदिर क्षेत्र को लेकर कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। 2011 की झड़पों में भी 20 लोगों की जान गई और हजारों लोग विस्थापित हुए।अब, एक दशक बाद यह संघर्ष फिर से उसी रूप में लौट आया है, और इस बार एयरस्ट्राइक और बमबारी तक की नौबत आ गई है।

राजनीतिक अस्थिरता और आरोप-प्रत्यारोप

इस विवाद का असर थाईलैंड की आंतरिक राजनीति पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री पेतोंगटार्न शिनावात्रा को जुलाई की शुरुआत में कंबोडियाई पूर्व पीएम हुन सेन से फोन पर हुई बातचीत को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर नैतिक उल्लंघन के आरोप लगे और उन्हें जांच तक के लिए निलंबित कर दिया गया।इससे स्पष्ट है कि मंदिर विवाद न केवल सीमाई विवाद है, बल्कि यह राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण बन गया है।जो मंदिर सदियों से आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक रहा है, वह आज गोलियों और बमों की मार झेल रहा है। एक ऐसा स्थल, जो भगवान शिव की उपासना का केंद्र है, अब राजनीतिक संघर्ष और सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुका है।

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई: शेयरों में गिरावट, सरकार और विपक्ष के सवाल

अनिल अंबानी, एक समय भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक, आजकल फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनकी कंपनियों की सक्सेस नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और उससे जुड़ा हंगामा है। 24 जुलाई 2025 से शुरू हुई ED की रेड, जो 48 घंटे से ज्यादा समय तक चली, ने अनिल अंबानी की कंपनियों—रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर—को हिलाकर रख दिया। इन छापों के बाद इन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जो दो दिनों में 10% तक नीचे चले गए। सवाल यह है कि क्या यह गिरावट सिर्फ ED की कार्रवाई का नतीजा थी? सरकार ने इसमें क्या रोल निभाया? और विपक्ष ने इस मामले को कैसे उठाया? आइए, इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं।

ED की रेड: क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 24 जुलाई 2025 को अनिल अंबानी की कंपनियों और यस बैंक से जुड़े 3000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड मामले में छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई मुंबई और दिल्ली में 35 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हुई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 लोग ED के रडार पर थे। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हो रही है और इसका आधार CBI की दो FIRs के साथ-साथ SEBI, नेशनल हाउसिंग बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे संस्थानों की जानकारी है।

ED का कहना है कि यस बैंक से लिए गए लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि लोन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं, जैसे बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल, बिना ड्यू डिलिजेंस के निवेश, और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस कार्रवाई का कोई सीधा असर अपने बिजनेस पर न होने की बात कही, लेकिन शेयर मार्केट में निवेशकों का भरोसा डगमगा गया।

यह रेड 26 जुलाई तक, यानी तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे मामला और गंभीर हो गया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा।

शेयरों में 10% की गिरावट: ED रेड का असर या कुछ और?

ED की छापेमारी की खबर के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 24 और 25 जुलाई 2025 को इन दोनों कंपनियों के शेयर 5-5% के लोअर सर्किट पर बंद हुए, जिसका मतलब है कि दो दिनों में कुल 10% की गिरावट। रिलायंस पावर का शेयर 61.77 रुपये से फिसलकर 58.09 रुपये पर आ गया, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 377 रुपये से गिरकर 359.85 रुपये पर पहुंच गया। इस गिरावट से रिलायंस पावर का मार्केट कैप 24,720 करोड़ रुपये और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 14,690 करोड़ रुपये रह गया।

क्या यह गिरावट सिर्फ ED की रेड की वजह से थी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ED की कार्रवाई ने निवेशकों में पैनिक क्रिएट किया, जिससे भारी बिकवाली हुई। लेकिन कुछ अन्य फैक्टर्स भी इस गिरावट में शामिल हो सकते हैं। मसलन, भारतीय शेयर मार्केट में 24 जुलाई को सेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी 160 अंक नीचे गिरा, जो मार्केट के ओवरऑल मूड को दिखाता है। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने रिलायंस पावर में अपनी हिस्सेदारी 13 बेसिस पॉइंट्स कम करके 2.43% कर दी, जिसने भी निवेशकों का कॉन्फिडेंस और हिलाया।

हालांकि, यह भी सच है कि इन कंपनियों के शेयर पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले एक साल में 146% और रिलायंस पावर ने 139% का रिटर्न दिया था। इस लिहाज से, ED की रेड ने उस तेजी पर ब्रेक लगा दिया, जो इन कंपनियों के डेट रिडक्शन, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और डिफेंस सेक्टर में नए ऑर्डर्स की वजह से थी।

सरकार की भूमिका: जांच में क्या है उसका रोल?

ED एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसकी कार्रवाई को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इसमें सरकार का कोई दबाव या रोल होता है? इस मामले में, ED की रेड CBI की FIRs और अन्य नियामक संस्थानों की जानकारी पर आधारित थी। सरकार ने इस जांच में सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन यह कार्रवाई केंद्र सरकार के मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ सख्त रुख को दिखाती है।

अनिल अंबानी की कंपनियां पहले भी कई बार जांच के दायरे में रही हैं, खासकर रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) को लेकर। लेकिन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने साफ किया कि उनकी इन कंपनियों से कोई फाइनेंशियल या बिजनेस कनेक्शन नहीं है। फिर भी, ED की इस कार्रवाई को कुछ लोग सरकार की सख्त नीतियों का हिस्सा मान रहे हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेज पर नकेल कसना चाहती है।

दूसरी तरफ, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हाल ही में डिफेंस सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली थी। इसने 155 मिमी के आर्टिलरी गोला-बारूद डिजाइन और डेवलप किए, जो मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री से इसे 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। ऐसे में, ED की कार्रवाई को कुछ लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच टकराव के रूप में भी देख रहे हैं।

विपक्ष का रुख: क्या उठे सवाल?

ED की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने इस मामले पर ज्यादा मुखरता नहीं दिखाई, लेकिन कुछ नेताओं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल जरूर उठे। विपक्ष का एक धड़ा इसे सरकार की "चुनिंदा कार्रवाई" बता रहा है। कुछ X पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि ED की रेड्स अक्सर उन बिजनेस हाउसेज पर होती हैं, जो सरकार के साथ तालमेल नहीं रख पाते। हालांकि, ये दावे पुख्ता सबूतों पर आधारित नहीं हैं और इन्हें अफवाह के तौर पर ही देखा जा रहा है।

विपक्षी दलों ने इस मामले में कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे कॉरपोरेट सेक्टर में भ्रष्टाचार का उदाहरण बताकर सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। दूसरी तरफ, कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर अनिल अंबानी की कंपनियां डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में काम कर रही हैं, तो क्या यह कार्रवाई उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है?

विपक्ष का यह रुख नया नहीं है। पहले भी ED और CBI की कार्रवाइयों को लेकर सरकार पर "वेंडेटा पॉलिटिक्स" के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस मामले में कोई ठोस सबूत या बयान सामने नहीं आया, जिससे यह साफ हो कि विपक्ष इसे पॉलिटिकल इश्यू बनाना चाहता है।

भविष्य का रास्ता: अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के लिए क्या?

ED की रेड और शेयरों में गिरावट के बावजूद, अनिल अंबानी की कंपनियां पूरी तरह से बैकफुट पर नहीं हैं। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल के सालों में अपने कर्ज को काफी हद तक कम किया है। रिलायंस पावर ने 5,338 करोड़ का कर्ज चुकाया, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी क्रेडिट रेटिंग को 'IND D' से 'IND B/Stable/IND A4' तक अपग्रेड करवाया।

कंपनियों ने क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में भी बड़ा दांव खेला है। रिलायंस पावर ने भूटान में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और 770 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट हासिल किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस सेक्टर में 155 मिमी आर्टिलरी गोला-बारूद के प्रोडक्शन के साथ मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रही है।

लेकिन ED की कार्रवाई ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह जांच लंबी चली, तो शेयरों में और गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ, अगर कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करती हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखती हैं, तो यह गिरावट अस्थायी हो सकती है।

एक नाजुक संतुलन

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ED की रेड ने न सिर्फ शेयर मार्केट में हलचल मचाई, बल्कि बिजनेस, पॉलिटिक्स, और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट के बीच एक नाजुक संतुलन को उजागर किया। शेयरों में 10% की गिरावट ED की कार्रवाई का सीधा नतीजा थी, लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूड और LIC की हिस्सेदारी में कमी ने भी इसमें रोल निभाया। सरकार की भूमिका इस मामले में अप्रत्यक्ष रही, लेकिन विपक्ष के सवालों ने इस कार्रवाई को पॉलिटिकल टच दे दिया।

अनिल अंबानी के लिए यह एक टेस्टिंग टाइम है। उनकी कंपनियां क्लीन एनर्जी और डिफेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में काम कर रही हैं, लेकिन फाइनेंशियल अनियमितताओं के पुराने घाव अभी भी उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। क्या अनिल अंबानी इस संकट से उबर पाएंगे? यह सवाल न सिर्फ उनके लिए, बल्कि लाखों निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो उनके शेयरों में अपने पैसे लगाए बैठे हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

कुछ इश्क़ किया कुछ काम किया

पीयूष मिश्रा

हिंदी सिनेमा से संबद्ध लोकप्रिय गीतकार-कवि और पटकथा लेखक।

वो काम भला क्या काम हुआ
जिस काम का बोझा सर पे हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिस इश्क़ का चर्चा घर पे हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो मटर सरीखा हल्का हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ना दूर तहलका हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें ना जान रगड़ती हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ना बात बिगड़ती हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें साला दिल रो जाए

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो आसानी से ही जाए

वो काम भला क्या काम हुआ
जो मज़ा नहीं दे व्हिस्की का

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ना मौक़ा सिसकी का

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसकी ना शक्ल 'इबादत' हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसकी दरकार 'इजाज़त' हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो कहे 'घूम और ठग ले बे'

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो कहे 'चूम और भग ले बे'

वो काम भला क्या काम हुआ
कि मज़दूरी का धोखा हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो मजबूरी का मौक़ा हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें ना ठसक सिकंदर की

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ना ठरक हो अंदर की

वो काम भला क्या काम हुआ
जो कड़वी घूँट सरीखा हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो सबकी सुन के होता हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो 'वातानुकूलति' हो बस

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो 'हाँफ़ के कर दे चित' बस

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें ना ढेर पसीना हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो ना भीगा ना झीना हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें ना लहू महकता हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो इक चुंबन में थकता हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें अमरीका बाप बने

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो वियतनाम का शाप बने

वो काम भला क्या काम हुआ
जो बिन लादेन को भा जाए

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो चबा... 'मुशर्रफ़' खा जाए

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें संसद की रंगरलियाँ

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो रँगे गोधरा की गलियाँ

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसका सामाँ ख़ुद 'बुश' हो ले

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो एटम बम से ख़ुश हो ले

वो काम भला क्या काम हुआ
जो 'दुबई... फ़ोन पे' हो जाए

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो मुंबई आ के 'खो' जाए

वो काम भला क्या काम हुआ
जो 'जिम' के बिना अधूरा हो
वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो हीरो बन के पूरा हो

वो काम भला क्या काम हुआ
कि सुस्त ज़िंदगी हरी लगे

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि 'लेडी मॅकबैथ' परी लगे

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें चीख़ों की आशा हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो मज़हब, रंग और भाषा हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो ना अंदर की ख़्वाहिश हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो पब्लिक की फ़रमाइश हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो कम्प्यूटर पे खट्-खट् हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ना चिट्ठी ना ख़त हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जिसमें सरकार हज़ूरी हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें ललकार ज़रूरी हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो नहीं अकेले दम पे हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो ख़तम एक चुंबन पे हो

वो काम भला क्या काम हुआ
कि 'हाथ जकड़ गई उँगली बस'

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि 'हाय पकड़ ली उँगली बस'

वो काम भला क्या काम हुआ
कि मनों उबासी मल दी हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जिसमें जल्दी ही जल्दी हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो ना साला आनंद से हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो नहीं विवेकानंद से हो

वो काम भला क्या काम हुआ
जो चंद्रशेखर आज़ाद ना हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो भगत सिंह की याद ना हो

वो काम भला क्या काम हुआ
कि पाक जुबाँ फ़रमान ना हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो गांधी का अरमान ना हो

वो काम भला क्या काम हुआ
कि खाद में नफ़रत बो दूँ मैं

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि हसरत बोले रो दूँ मैं

वो काम भला क्या काम हुआ
कि खट्ट तसल्ली हो जाए

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि दिल ना टल्ली हो जाए

वो काम भला क्या काम हुआ
इंसान की नीयत ठंडी हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि जज़्बातों में मंदी हो

वो काम भला क्या काम हुआ
कि क़िस्मत यार पटक मारे

वो इश्क़ भला कया इश्क़ हुआ
कि दिल मारे ना चटखारे

वो काम भला क्या काम हुआ
कि कहीं कोई भी तर्क नहीं

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि कढ़ी खीर में फ़र्क़ नहीं

वो काम भला क्या काम हुआ
चंगेज़ ख़ान को छोड़ दें हम

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
इक और बाबरी तोड़ दें हम

वो काम भला क्या काम हुआ
कि आदम बोले मैं ऊँचा

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि हव्वा के घर में सूखा
वो काम भला क्या काम हुआ
कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
जो मारलन ब्रांडो भूल के हो

वो काम भला क्या काम हुआ
'परफ़ार्मेंस' अपने बाप का घर

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि मॉडल बोले मैं 'एक्टर'

वो काम भला क्या काम हुआ
कि टट्टी में भी फ़ैक्स मिले

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि भट्ठी में भी सेक्स मिले

वो काम भला क्या काम हुआ
हर एक 'बॉब डी नीरो' हो

वो इश्क़ भला क्या इश्क़ हुआ
कि निपट चूतिया हीरो हो

झालावाड़ स्कूल हादसा: एक त्रासदी जो सवालों का पहाड़ खड़ा करती है

राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई 2025 को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। सरकारी स्कूल की जर्जर छत ढहने से सात मासूम बच्चों की जान चली गई और 29 बच्चे घायल हो गए। यह घटना सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान हुई, जब बच्चे कक्षा में इकट्ठा थे। इस हादसे ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठा दिए। इस लेख में हम इस त्रासदी के हर पहलू को देखेंगे—क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, भारत में स्कूलों की स्थिति, विपक्ष के सवाल, और पिछले पांच सालों में ऐसे हादसों का लेखा-जोखा।

झालावाड़ में क्या हुआ? एक दर्दनाक हकीकत

25 जुलाई 2025 की सुबह, झालावाड़ के मनोहरथाना ब्लॉक में पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए जमा थे। बारिश की वजह से प्रार्थना बाहर के बजाय कक्षा में हो रही थी। तभी सातवीं कक्षा के कमरे की छत अचानक ढह गई। इस हादसे में सात बच्चों—पायल (14), प्रियंका (14), कार्तिक (8), हरीश (8), मीना, कान्हा, और सतीश—की मौत हो गई। 29 बच्चे घायल हुए, जिनमें से नौ की हालत गंभीर है और वे आईसीयू में हैं।

स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गईं। घायलों को मनोहरथाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, और गंभीर मामलों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। एक परिवार ने अपने इकलौते बेटे कार्तिक को खो दिया, तो एक पिता छोटूलाल ने अपने दोनों बच्चों—कान्हा और मीना—को एक ही अर्थी पर विदा किया।

हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जो इस त्रासदी की भयावहता को दिखाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की छत से पहले भी कंकड़ गिरने की शिकायतें थीं, लेकिन शिक्षकों ने बच्चों को डांटकर चुप करा दिया। यह हादसा केवल एक इमारत के ढहने की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है।

जिम्मेदारी किसकी? लापरवाही का खेल

इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? यह सवाल हर किसी के मन में है। प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रशासन, जिला प्रशासन, और शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन 1991-94 में बना था और इसकी हालत बरसों से खराब थी। बारिश ने इसकी कमजोर नींव को और बिगाड़ दिया।

शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई 2025 को सभी स्कूलों को जर्जर भवनों की जांच और मरम्मत के आदेश दिए थे। लेकिन पिपलोदी स्कूल में कोई निरीक्षण नहीं हुआ। स्थानीय सीबीईओ ने दावा किया कि स्कूल सुरक्षित है, जो बाद में झूठा साबित हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ा, कहते हुए कि पिछले पांच सालों में स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार भी इस मामले में चूक गई।

जिला कलेक्टर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, और स्कूल प्रिंसिपल पर भी सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद कार्यवाहक प्रिंसिपल सहित पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? ग्रामीणों का गुस्सा इस बात पर है कि उनकी शिकायतों को बार-बार नजरअंदाज किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और पांच दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपये और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया गया। नए स्कूल भवनों में कक्षा कक्ष मृतक बच्चों के नाम पर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा और नौकरी इस दुख को कम कर सकती है?

खस्ताहाल स्कूल: भारत की कड़वी सच्चाई

झालावाड़ हादसा कोई इकलौता मामला नहीं है। देशभर में सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं। राजस्थान में ही 900 से ज्यादा स्कूल जर्जर हैं, जिनमें से 294 को इस्तेमाल के लायक नहीं माना गया। फिर भी, इनमें पढ़ाई जारी है। ओडिशा में 12,343, महाराष्ट्र में 8,071, और पश्चिम बंगाल में 4,269 स्कूल खराब हालत में हैं।

हनुमानगढ़ के स्कूलों की स्थिति भी बदतर है। वहां की दीवारों में दरारें हैं, और छतें कभी भी गिर सकती हैं। शिक्षकों और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देशभर में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए सरकारें हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। राजस्थान में पिछले दो सालों में 1500 करोड़ रुपये खर्च हुए, और 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। लेकिन पिपलोदी स्कूल मरम्मत की लिस्ट में भी नहीं था।

कई स्कूल पुरानी इमारतों में चल रहे हैं, जिनका नियमित रखरखाव नहीं होता। खराब सामग्री, गलत डिजाइन, और सुरक्षा नियमों की अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार है। बाढ़, भूकंप, और भारी बारिश जैसे प्राकृतिक कारण भी इन हादसों को बढ़ाते हैं। स्कूलों में नियमित सुरक्षा ऑडिट और बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की कमी एक बड़ी समस्या है।

विपक्ष का हंगामा: सवाल जो गूंज रहे हैं

विपक्ष ने इस हादसे को सरकार की नाकामी का सबूत बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जर्जर स्कूलों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। सचिन पायलट ने इसे "आपराधिक लापरवाही" करार दिया और गहन जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने जर्जर स्कूलों को चिह्नित करने और उनकी मरम्मत के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। राजस्थान विधानसभा में जनवरी-मार्च 2025 के सत्र में आठ विधायकों ने जर्जर स्कूलों पर सवाल उठाए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर स्कूलों को पहले चिह्नित कर बच्चों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाता, तो यह हादसा टाला जा सकता था।

विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार नेताओं और मंत्रियों के लिए सड़कें तो तुरंत बनवा देती है, लेकिन स्कूलों की मरम्मत के लिए फंड अटके रहते हैं। यह सवाल उठ रहा है कि जब 10 दिन पहले ही स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए थे, तो पिपलोदी स्कूल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

पिछले पांच सालों में स्कूल हादसे: एक डरावना आंकड़ा

पिछले पांच सालों में देशभर में स्कूल हादसों की संख्या चौंकाने वाली है। हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, कुछ बड़े हादसों ने देश का ध्यान खींचा है।

2024, पाली, राजस्थान: एक स्कूल टूर बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। सौभाग्य से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन यह स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है।

2023, वडोदरा, गुजरात: एक निजी स्कूल की चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। दो बच्चों की मौत हुई और कई घायल हुए। जांच में खराब सामग्री का इस्तेमाल सामने आया।

2021, दिल्ली: एक स्कूल की जर्जर इमारत में हादसा हुआ। रखरखाव की कमी इसका कारण थी। दिल्ली सरकार ने इसके बाद सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने की बात कही थी।

2001, भुज, गुजरात: भूकंप के कारण कई स्कूल ध्वस्त हो गए, जिसमें कई बच्चों की जान गई। इसने भूकंप-रोधी इमारतों की जरूरत को उजागर किया।

इन हादसों से साफ है कि स्कूलों की सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जर्जर इमारतों, खराब रखरखाव, और लापरवाही के कारण बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। झालावाड़ हादसे ने एक बार फिर इस समस्या को सामने ला दिया है।

अब जागने का वक्त है

झालावाड़ स्कूल हादसा एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। यह त्रासदी केवल एक स्कूल की छत ढहने की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी, लापरवाही, और जवाबदेही की कमी का सबूत है। सरकार ने जांच और मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन क्या यह काफी है? स्कूलों की जर्जर हालत, सुरक्षा ऑडिट की कमी, और प्रशासनिक उदासीनता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

विपक्ष के सवाल जायज हैं—जब शिकायतें पहले से थीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देशभर में हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं। इनका सर्वे, मरम्मत, और नियमित ऑडिट जरूरी है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें न केवल स्कूलों की इमारतें, बल्कि पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं—इसमें सुरक्षित माहौल भी शामिल है। क्या हम अब जागेंगे, या यह त्रासदी भी एक और फाइल में दबकर रह जाएगी?

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

तंत्र योग का जादू: जवानी और सेहत का राज़

तंत्र योग, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी जोड़ती है। ये सिर्फ सेक्स या शारीरिक सुख की बात नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपनी ऊर्जा को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की कला सिखाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई जवानी और सेहत की तलाश में है, तंत्र योग एक अनोखा रास्ता दिखाता है। इस लेख में, हम तंत्र योग के फायदों, इसके डाइट से जुड़े नजरिए, और बीमारियों को ठीक करने की इसकी खासियत को आसान और आधुनिक हिंदी में समझेंगे।

जवानी का झरना: तंत्र योग का कमाल

तंत्र योग को अक्सर "जवानी का झरना" कहा जाता है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये योग शरीर के मूलाधार चक्र (sex chakra) पर फोकस करता है, जिसे तांत्रिक मान्यताओं में जीवन शक्ति का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि सेक्स ग्लैंड्स हमारे शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक डॉ. यूजेन स्टाइनच ने पाया कि सेक्स हार्मोन्स न सिर्फ जवानी को बनाए रखते हैं, बल्कि इनके कम होने से बुढ़ापा जल्दी आता है। तंत्र योग इस ऊर्जा को जागृत करके शरीर में नई ताजगी लाता है।

इसके अलावा, तंत्र योग में "मैथुन" (संयमित और आध्यात्मिक यौन क्रिया) के जरिए शरीर की दो धाराओं—पुरुष और स्त्री ऊर्जा—को एक करने पर जोर दिया जाता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ताजगी भी देती है। तंत्र सिखाता है कि डर, खासकर बुढ़ापे और बीमारी का डर, हमारे शरीर में एक तरह का जहर पैदा करता है। इसके उलट, तंत्र योग प्रेम और एकजुटता को बढ़ावा देता है, जो तनाव को कम करके जवानी को लंबे समय तक बनाए रखता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें न सिर्फ फिजिकली फिट रखता है, बल्कि हमारी सोच को भी जवान और एक्टिव बनाता है।

तंत्र योग की खास बात ये है कि ये हमें अपने शरीर की ऊर्जा को समझने और उसे बैलेंस करने की ट्रेनिंग देता है। नियमित साधना से न्यूरोहार्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं, जो शरीर को री-एनर्जाइज करते हैं। इससे न सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि दिमाग भी तेज और क्रिएटिव बनता है। आज की यूथ, जो हमेशा फिट और यंग दिखना चाहती है, तंत्र योग से बहुत कुछ सीख सकती है। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक तरीका है जो जवानी को नेचुरली बढ़ाता है।

खानपान का तंत्र: स्वाद और सेहत का मेल

तंत्र योग में खानपान को लेकर कोई सख्त नियम नहीं हैं, लेकिन ये एक बैलेंस्ड और माइंडफुल डाइट की सलाह देता है। ज्यादातर तांत्रिक योगी मांस और शराब से परहेज करते हैं, खासकर पंचतत्व रीति के बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। भारतीय शास्त्रों में सूरज की रोशनी से भरपूर खाने की सलाह दी जाती है, जैसे चावल का मांड, छाछ, जौ, फल, जड़ें, केसर और दलिया। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि योगी को ऐसे खाने खाने चाहिए जो मन को शांत और केंद्रित रखें।

तंत्र योग की खास बात ये है कि ये हर इंसान की जरूरतों को समझता है। मॉडर्न लाइफ में, जहां हर देश और संस्कृति का खानपान अलग है, तंत्र योग कहता है कि आपको अपने शरीर के हिसाब से खाना चाहिए। पंडित चटर्जी, एक तांत्रिक गुरु, कहते हैं कि खाने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। उनका मानना है कि खाना वही खाएं जो आपकी साधना में मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं, तो भारी और मुश्किल से पचने वाला खाना अवॉइड करें।

तंत्र योग में शहद को बहुत खास माना जाता है। इसे घी के साथ 3:1 के अनुपात में मिलाकर सुबह-शाम लेने की सलाह दी जाती है। ये न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि बुढ़ापे को भी दूर रखता है। एक मशहूर भारतीय शिक्षाविद् श्रीजुत मालवीय ने इस नुस्खे से अपनी जवानी को 20 साल तक बनाए रखा था। पश्चिमी देशों में जहां लोग ज्यादा खाने की आदत से जूझते हैं, तंत्र योग कम खाने की सलाह देता है—सुबह का नाश्ता पेट का एक-चौथाई, दोपहर का तीन-चौथाई, और रात का आधा। ये आसान नियम शरीर को हल्का और दिमाग को शांत रखता है।

बीमारियों से जंग: तंत्र योग की ताकत

तंत्र योग न सिर्फ जवानी को बनाए रखता है, बल्कि बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। इसका फोकस शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने पर है, जिससे मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार होता है। तंत्र योग में सांस की तकनीक (प्राणायाम) और खास आसनों का इस्तेमाल करके शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाया जाता है। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर हिस्से को री-एनर्जाइज करती है, जिससे बीमारियां ठीक होने में मदद मिलती है।

उदाहरण के लिए, स्वामी सदानंद जैसे तांत्रिक गुरुओं ने प्राण शक्ति का इस्तेमाल करके कई लोगों की गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। एक बार स्वामी सदानंद ने प्राण प्रतिष्ठा तकनीक से एक व्यक्ति के दौरे (epileptic fits) को ठीक करने में मदद की। तंत्र योग का मानना है कि नाभि केंद्र (navel center) हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां से कई अंगों की सेहत कंट्रोल होती है। इस केंद्र को एक्टिव करने से पाचन, किडनी, और दूसरी समस्याएं ठीक हो सकती हैं।

आधुनिक रिसर्च भी तंत्र योग के फायदों को सपोर्ट करती है। हार्वर्ड हेल्थ और जॉन्स हॉपकिन्स जैसे संस्थानों के स्टडीज बताते हैं कि योग, खासकर तंत्र योग, तनाव, डिप्रेशन, और हृदय रोगों को कम करने में मदद करता है। ये बीमारियां आज की यूथ में आम हैं, और तंत्र योग इनसे निपटने का एक नेचुरल तरीका है। खास बात ये है कि तंत्र योग आपको अपने शरीर को खुद ठीक करने की ताकत देता है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी सेहत के मालिक हैं, न कि कोई बाहर का डॉक्टर या दवा।

मॉडर्न लाइफ में तंत्र योग: यूथ के लिए टिप्स

आज की फास्ट-पेस्ड लाइफ में तंत्र योग को अपनाना आसान नहीं लगता, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है। तंत्र योग कहता है कि छोटे-छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले, रोज़ाना कम से कम एक मील पैदल चलें, हाथों को स्विंग करते हुए और हथेलियों को आगे की तरफ रखते हुए। ये आसान एक्सरसाइज आपकी रीढ़ को लचीला और एनर्जेटिक रखती है।

इसके अलावा, अपने पैरों की देखभाल करें। तंत्र योग में पैरों के अंगूठों को खास माना जाता है क्योंकि ये नाड़ियों के टर्मिनल पॉइंट्स हैं। नहाने के बाद इन्हें नारियल तेल या बादाम तेल से मसाज करें। ये छोटा सा स्टेप आपकी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। शहरों में रहने वाले लोग, जहां हवा में पॉजिटिव आयन्स की मात्रा ज्यादा होती है, को चाहिए कि वो समय-समय पर खुले मैदानों, समुद्र तट, या झील के किनारे जाएं। वहां की नेगेटिव आयन्स वाली हवा तनाव को कम करती है और शरीर को रिलैक्स करती है।

तंत्र योग का सबसे बड़ा सबक है—डर को छोड़ें और प्रेम को अपनाएं। बुढ़ापे और बीमारी का डर हमारे शरीर को कमजोर करता है। इसके उलट, तंत्र योग हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाकर न सिर्फ जवानी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने शरीर, मन, और आत्मा को एक करने की ताकत देता है।

तंत्र योग कोई जटिल विज्ञान नहीं है; ये एक लाइफस्टाइल है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज की यूथ के लिए, जो फिटनेस और मेंटल पीस की तलाश में है, तंत्र योग एक गेम-चेंजर हो सकता है। तो, क्यों न इस जादुई पद्धति को अपनाकर अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और जवानी का रंग भरा जाए?

हवाई हादसे में बुझ गया दो परिवारों का चिराग

एक भारत का बेटा भी शामिल

@ आनंद मीणा

कनाडा के न्यूफाउंडलैंड प्रांत स्थित डियर लेक क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक भारतीय नागरिक गौतम संतोष (27) भी शामिल हैं। यह हादसा 26 जुलाई की शाम उस समय हुआ, जब एक छोटा वाणिज्यिक सर्वेक्षण विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद डियर लेक क्षेत्रीय हवाई अड्डे से लगभग एक किलोमीटर दक्षिण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुर्घटनाग्रस्त विमान एक पाइपर पीए-31 नवाजो था, जिसे किसिक एरियल सर्वे इंक के नाम से पंजीकृत किया गया था। इस विमान में दो व्यक्ति सवार थे — पायलट, जिसकी उम्र 54 वर्ष थी, और एकमात्र यात्री गौतम संतोष, जो भारत के नागरिक थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने पुष्टि की कि दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।विमान जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में वह हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना स्थल डियर लेक हवाई अड्डे के पास स्थित ट्रांस-कनाडा हाईवे (TCH) के करीब था, जिसे तत्काल प्रभाव से कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। आपातकालीन कर्मियों और जांच एजेंसियों को घटनास्थल पर पहुंचने में सहायता के लिए यह कदम उठाया गया।

भारतीय नागरिक की मृत्यु पर गहरा शोक

टोरंटो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया,"गहरे दुख के साथ हम भारतीय नागरिक गौतम संतोष के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने न्यूफाउंडलैंड के डियर लेक के पास एक वाणिज्यिक सर्वेक्षण विमान से जुड़ी दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी।"महावाणिज्य दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मृतक के परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।

विमान कंपनी ने जताया दुख, जांच जारी

किसिक एरियल सर्वे इंक के मालिक एंड्रयू नेस्मिथ ने एक भावुक बयान में कहा,"हम इस क्षति से स्तब्ध और दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों और उनके प्रियजनों के साथ हैं। फिलहाल हम मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, यह जानकारी संबंधित अधिकारी ही साझा करेंगे।"इस हादसे की जांच कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड (TSB) द्वारा की जा रही है। बोर्ड ने बताया कि हादसे की जांच प्रारंभिक चरण में है और विभिन्न तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच में मौसम, विमान की तकनीकी स्थिति, पायलट का अनुभव और उड़ान मार्ग जैसे सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।

स्थानीय समुदाय में शोक की लहर

डियर लेक और आसपास के क्षेत्रों में इस दुर्घटना ने शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय प्रशासन, राहत एजेंसियां और विमानन सुरक्षा अधिकारी इस हादसे को लेकर सतर्कता और सहयोग के साथ काम कर रहे हैं।यह विमान हादसा एक बार फिर यह याद दिलाता है कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। दो परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, और अब वे न्याय व जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं। भारत और कनाडा दोनों देशों के अधिकारी मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि मृतकों के परिवारों को न्याय, समर्थन और यथासंभव सहायता मिल सके।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

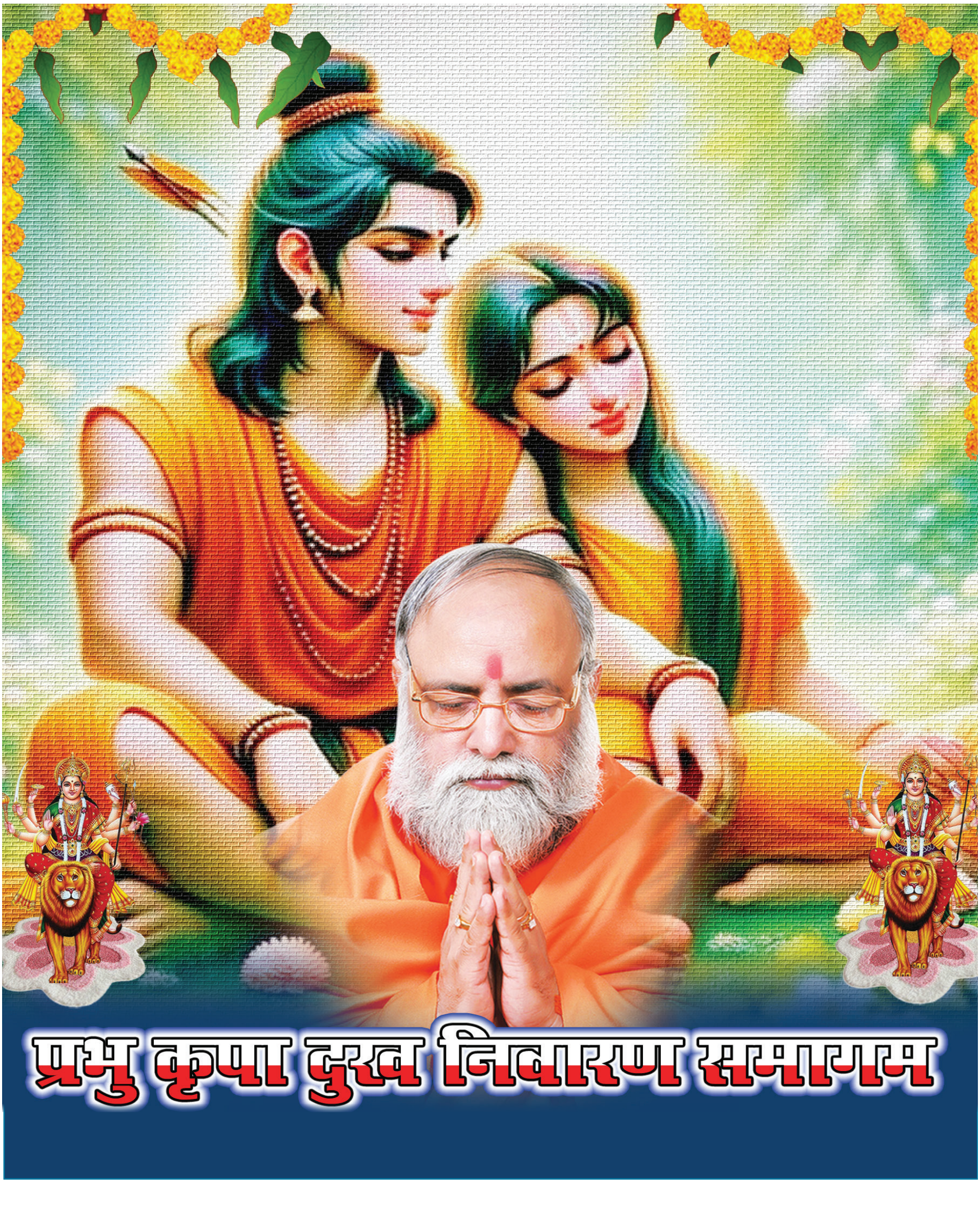

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries